ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-5* June- 2020
Innovation The Research Concept

दुनिया के समक्ष चुनौती पेश कर रहा चीन : एक विश्लेषण

China is Challenging The World: An Analysis

Paper Submission: 15/06/2020, Date of Acceptance: 25/06/2020, Date of Publication: 26/06/2020

वीरेन्द्र चावरे
असिस्टेंट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान
अध्ययनशाला,
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन,
म.प्र., भारत

सारांश

चीन का बढ़ता दबदबा दुनिया के लिए खतरा बन गया है। दुनिया के सामने चीन जैसी चुनौती और खतरे पेश कर रह है वैसा कोई दुसरा देश नहीं। चीन अपने शांतिपूर्ण उदय का मुखौंटा उतार कर शक्ति की राजनीति पर उतर आया है। चीन की आक्रामक और विस्तारवादी नीति से दुनिया के देशों में चीन के प्रति अविश्वास बढ़ा है। ऐसे में चीन से प्रताड़ित और उसके विरोधी और उसके विरूद्ध एक समान सोच रखने वाले देश चीन के खिलाफ मौर्चा खोल सकते है। चीन के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ने न केवल भारत को बल्कि दुनिया के अन्य देशों को भी खतरे में डाल दिया है। चीन और अमेरिकी तनाव ने भी दुनिया को एक नए शीतयुद्ध में धकेल दिया है।

China's growing dominance has become a threat to the world. No other country is presenting a challenge and danger like China to the world. China has come down on the politics of power by masking its peaceful rise. China's aggressive and expansionary policy has led to increased distrust of China among the countries of the world. In such a situation, the persecuted and his opponents against China and those with similar thinking can open a war against China. China's irresponsible behavior has not only put India but also other countries of the world at risk. China and US tensions have also pushed the world into a new cold war.

मुख्य शब्द : चुनौती, चीन, भारत, अमेरिका, कोरोना वायरस।
Challenge, China, India, US, Corona Virus.

प्रस्तावना

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही विश्व के फलक पर चीन दुनिया को अपने होने का अहसास कराता रहा है। ''युद्ध से पहले भी और युद्ध के दौरान भी अमेरिका के मन में चीन को लेकर विशेष चिंता रही थी। हालांकि अब उसका पहले की तरह जिक्र नहीं होता है। नई विश्व व्यवस्था में चीन को साम्यवाद के उदय से पहले भी हमेशा एक महाशक्ति के तौर पर देखा था।''[1]

साम्यवाद के उदय के बाद से ही अमेरिका के मन में भी चीन को लेकर चिंता रही थी। पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन को स्थायी सदस्य नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि इसमें रूस और चीन एक साथ दो साम्यवादी देश हो जाते। इससे लोकतंत्र और शक्ति संतुलन पर भी असर हो सकता था। रूस और चीन के मतभेदों ने चीन को अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बनने की राह पर धकेल दिया। 20 वीं सदी तक भी चीन को एक आर्थिक, सैन्य और तकनीकी खतरे के रूप में नहीं देखा जाता था जैसा की आज। चीन दुनिया के सामने जिस तरह की चुनौती और खतरे पेश कर रहा है वैसा कोई दुसरा देश नहीं कर रहा।

शोध प्रविधि

इस शोध पत्र में एतिहासिक एवं विश्लेषणात्म पद्ति का उपयोग किया गया है। इसमें द्वितीयक स्त्रोतों के आधार पर विश्लेषण किया गया है।

शोध के उद्देश्य

इस शोध पत्र में चीन से उत्पन्न खतरों एवं चुनौतियों की खोज एवं विश्लेषण करना।

वायरस के अलावा चीन से और भी खतरे

सच पर पर्दा डाल और झुठ के सहारे चीन वुहान से शुरू हुए वायरस पर काबु पाने में विफलता से पल्ला झाड़ने की कोशिश करता रहेगा, जबकि वायरस से दुनिया भर में लाखों लोगों की जान जा चुकी है और आर्थिक तबाही

का कोई और छोर नहीं है लेकिन वायरस को लेकर छल–कपट चीन के कम्युनिज्म से पेश आने वाला सबसे बुरा खतरा नहीं है। यह तो स्पष्ट लक्षण मात्र है। वायरस की शुरूआत तो किसी भी देश से हो सकती है, लेकिन जैसा खतरा और चुनौती चीन प्रस्तुत कर रहा है, कोई अन्य देश नहीं कर रहा।[2] जब से कोविड–19 की महामारी ने पुरी दुनिया को ऐतिहासिक संकट में डाला है। तब से चीन ने बड़ी ही चालाकी से इस बात को झुठलाने की कोशिश की है कि महामारी का संक्रमण चीन के वुहान से फैला है। यदि चीन ने प्रारम्भिक दिनों में ही सूचना को साझा कर दिया होता तो पूरी दुनिया खतरे में नहीं पड़ती। चीन ने न केवल सूचनाओं को नियंत्रित किया बल्कि यदि किसी ने इसके फैलने की सूचना देकर चीन की ताकत को चुनौती दी तो उसे भी बेरहमी से कुचल दिया गया। ये सब भविष्य में चीन से उत्पन्न होने वाले खतरे के लक्षण मात्र है।

स्वतंत्रता और लोकतंत्र को चुनौती

पिछले कुछ समय से चीन ने ढ़िठाई से अपनी पहुंच बढ़ाने की कार्यवाही की है। हांगकांग में चीन ने अग्रणी लोकतंत्रवादी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और चीनी सरकार की आलोचना को अपराध की श्रेणी में शामिल करने की कोशिश कर रहा है।[3] महामारी में पश्चिमी मॉडल के बुरी तरह फैल होने पर चीन ने इसे दुनिया के सामने लोकतांत्रिक मॉडल के फेल होने के तौर पर पेश किया जबकि वह अपने चीनी मॉडल को किसी भी लोकतंत्र से ज्यादा बेहतर और प्रभावी होने का प्रचार करता रहा। चीन ने यह दिखाने का प्रयास किया कि उसका मॉडल किसी भी वैश्विक स्वास्थ्य एवं अन्य समस्या से निपटने में ज्यादा बेहतर है। लेकिन चीन यह भूल रहा है कि दुनिया के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के साथ आजादी भी चाहिये जबकि चीन इससे मीलों दुर है। चीन की सबसे बड़ी कमी यह है कि उसमें भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों की तरह लचीलेपन और खुलेपन की कमी है। इसके विपरित चीन न केवल अपनी जनता पर शिकंजा कसता जा रहा है बल्कि उनके जीवन की स्वतंत्रता और मानव अधिकारों को भी खतरें मे डाल रहा है। पिछलें कुछ समय से उईगरों के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। पहले तिब्बत, शिन्जियांग और अब हांगकांग में चीन के स्वायत्ता के वादे खोखले साबित हो रहे है। इसी खतरे को पहचान कर ताईवान ने चीन के 'वन कन्ट्री टू सिस्टम' के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

डब्ल्यू एच ओ को कोरोना वायरस संबंधी डेटा देने में चीन की आनाकानी

न्यूज एजेंसी एपी ने अपनी रिपोर्ट ये दावा किया कि डब्ल्यूएचओ से चीन डेटा साझा करने में आनाकानी कर रहा था। चीन ने कोरोना से जुड़े जेनेटिक मेप, जीनोम की संरचना से जुड़े अहम तथ्य कई हफ्तें छिपाए रखे। यह भी शक है कि चीन ने रिसर्च की कई जानकारी डब्ल्यूएचओ से छिपाई। चीन की हरकतों से वैकसीन रिसर्च की शुरूआत करने में देरी हुई।[4] वास्तव में यदि समय पर चीन ने वायरस की उत्पत्ति और इससे जुड़े सही आंकड़े और जानकारी देने में भी आनाकानी की। चीन ने कोराना से जुड़े जेनेटिक मेप, जिनोम की संरचना से जुड़े अहम तथ्यों को कई हफ्तों तक छुपा कर रखा। यह वैश्विक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की है। यह एक तरह से चीन के सूचना युद्ध या डेटा चोरी की तरह ही है। यदि समय पर चीन वैक्सिन रिसर्च में दुनिया की मदद करता तो वैश्विक समुदाय को लाभ हो सकता था। चीन के इस कुप्रबंधन और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ने न केवल पूरी दुनिया को संकट में डाला बल्कि पूरी दुनिया को घुटने पर ला दिया। वैश्विक अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गयी।

चीन की मास्क डिप्लोमेसी

ऐसे में चीन ने मदद का मुखौटा पहन कर दुनिया के देशों में मेडिकल उपकरणों की सप्लाई की आड़ में एशिया, अफ्रिका, यूरोप के देशों में अपने आर्थिक बाजार ढूंढता रहा। 'चीन ने न केवल सूचना युद्ध छेड़ा बल्कि अपनी 'मास्क डिप्लोमेसी' के माध्यम से लेटिन अमेरिका में अपने मंसूबों को पूरा करने में लगा रहा।'[5] चीन ने यूरोपीय यूनियन में सेंध लगाने की भी कोशिश की। चीन इन देशों के भीतर की संवाद हिनता की कमजोरी और किसी भी संकट से निपटने की अपूर्ण तैयारी का नाजायज फायदा उठाते दिखा।[6] यह सब अमेरिका द्वारा इस मौके पर नेतृत्व का प्रदर्शन न करने से चीन को मनमानी करने का मौका मिला। यूरोपियन यूनियन को भविष्य में चीन के खतरे का सामना करना पड़ सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर चीन का प्रभाव

कोविड–19 के संकट काल में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) पर चीन के केन्द्रित होने और उसकी चापलूसी करने का आरोप लगा है। इससे दुनिया के देशों की डब्ल्यूएचओ पर से विश्वसनियता घटी है।[7] यहां तक कि डब्ल्यूएचओ की फैसले लेने वाली एक्जिक्यूटिव संस्था 'वर्ल्ड हेल्थ असेम्बली' में चीन ने दबाव डालकर ताईवान को बाहर करवा दिया इससे ताईवान सदस्य नहीं बन सका।[8] कुछ महीने पूर्व ही चीन को सूरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिलने के बाद चीनी राजदूत झांगजुंग ने ये स्पष्ट किया था कि चीन इस महामारी पर परिषद में जांच नहीं चाहता जो कि विश्व संस्था में चीन की मनमानी को दर्शाता है।

यह महत्वपूर्ण बात है कि डब्ल्यूएचओ के 72 वर्ष के इतिहास में अमेरिका ही इसका सबसे बड़ा दानदाता रहा है। पिछली फंडींग में अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ के कुल बजट का 15 प्रतिशत 893 मि. डॉलर दान दिया जब कि चीन ने मात्र 86 मि. डॉलर दिया फिर भी इस पर चीन का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है।[9] इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र की 15 विशिष्ट ऐजेंसीयों में से 4 में चीन के राजनयिक प्रमुख है जबकि दुनिया की सुपर पॉवर अमेरिका केवल एक एजेंसी का प्रमुख है। इसमें नीहित खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चीन डब्ल्यूएचओ की तरह बारी–बारी से अन्य एजेंसियों का भी दुरूपयोग नहीं करेगा। यानी चीन की मनमानी और विस्तारवादी नीति से वैश्विक संस्थाओं के प्रभावित होने का खतरा भी बढ़ गया है।

चीन का बढ़ता सैन्य बजट और सैन्य आधुनिकीकरण

चीन का लगातार बढ़ता सैन्य बजट और सैन्य आधुनिकीकरण दुनिया के अन्य देशों के लिए भी चिन्ता कारण बन गया है। 'क्योंकि 2049 में पिपुल्स रिपब्लीक ऑफ चायना की 100वीं वर्षगांठ पर चीन ग्लोबल लीडर बनने का लक्ष्य है।'[10] चीनी विशेषज्ञताओं के साथ एक मजबूत सैना का स्वप्न चीन को 2049 तक एक शक्ति का दर्जा दिलाएगा और दुनिया में चीन के प्रभुत्व को बढ़ाएगा।

चीन ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए कई मौर्चों पर अलग–अलग तरह के आधुनिक हथियारों को अपने बेड़े में शामिल किया। चीन इन हथियारों के दम पर अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है।[11] चीन ने अपने रक्षा बजट की पिछले साल को 177.6 अरब डॉलर से 6.6 प्रतिशत बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है। यह रकम भारत के रक्षा बजट का करीब तीन गुना है। अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे बड़ा बजट है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ न्यूज के मुताबिक लगातार पांचवे साल चीन के रक्षा बजट में 10 फिसदी से कम बढ़ोत्तरी की गई है। चीन के पास 20 लाख सैनिकों का दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य बल है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बीजिंग के सैन्य और आधुनिक हथियारों का विस्तार उसकी घोषणाओं के मुकाबले बहुत अधिक है। वहीं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) के मुताबिक 2019 में 232 बिलीयन डॉलर था। चीन के भारी रक्षा व्यय के चलते भारत और कई अन्य देशों को अपना रक्षा बजट बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा है, ताकि शक्ति संतुलन कायम रखा जा सके।[12]

चीन का 'बेल्ट एण्ड रोड़ इनिशिएटिव' प्रोजेक्ट

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी अतिमहत्वाकांक्षी परियोजना 'बेल्ट एण्ड रोड़ इनिशिएटिव' के तकह इसमें भागीदार देशों को बेतहाशा कर्ज बाट रहे है। 'अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री रेक्स टिलर्सन ने कहा था कि 'चीन कई देशों को अपने ऊपर निर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। वो जिन अनुबंधों को हासिल कर रहा वे पूरी तरह से अपारदर्शी है। नियम और शर्तो को लेकर स्पष्टता नहीं है। बेहिसाब कर्ज दिए जा रहे है और इससे गलत कामों को बढ़ावा मिलेगा। उन देशों की आत्मनिर्भरता तो खत्म होगी ही साथ में संप्रभुता पर भी असर पड़ेगा। चीन में क्षमता है कि वा आधारभूत ढाचों को विकास करे, लेकिन वो इसके नाम पर कर्ज के बोझ को बढ़ाने का काम कर रहा है।'[13] चीन से पाकिस्तान, श्रीलंका, लाओस, जिबूती, मालदीव, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो और किर्गिस्तान को भी बेशुमार कर्ज मिले है। यह माना जा रहा है कि जिस तरह से श्रीलंका को कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में अपना हम्बनटोटा पोर्ट सौंपना पड़ा उसी तरह बाकि देशों को भी करना पड़ेगा। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, म्यामांर और पाकिस्तान भी चीन के कर्ज के जाल में फंसते चले जा रहे है।[14] जाम्बिया पर भी कुल कर्ज 8.7 अरब डॉलर है और इसमें चीन का हिस्सा 6.4 अरब डॉलर है और यह भी इशारा मिला है कि बकाया नहीं चुकाने पर चीन हम्बनटोटा की तरह लुसाका के केनेश कौंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले सकता है।[15]

'बेल्ट एण्ड रोड़ इनिशिएटिव' प्रोजेक्ट में भागीदारी करने वाले देशों को चीन उच्च ब्याज दर पर कर्ज दे रहा है। कर्ज लेने वाले देशों को पूरा प्रोजेक्ट उस देश के हवाले करना पड़ता है। इससे कर्ज लेने वाले देशों की प्रगति भी प्रभावित होती है। जैसे–जैसे इन देशों पर चीन के कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। देशों में यह डर भी बढ़ता जा रहा है कि जो हश्र श्रीलंका और पाकिस्तान का हो रहा है वैसा ही इनके साथ भी न हो जाए। चीन इन देशों में अपना दबदबा और प्रभाव बढ़ाने के लिए कर्ज की रणनीति को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इससे कर्ज लेने वाले देशों की संप्रभुता और अधिकार को खतरा उत्पन्न हो गया है। चीन जिन देशों को कर्ज दे रहा है उन्हें चीन से सतर्क रहने की जरूरत है। इससे ने केवल भारत, आस्ट्रेलिया और अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की न केवल चिंता बल्कि दुनिया के समक्ष चीन से चुनौती भी मिल रही है।

चीन द्वारा डिजिटल मुद्रा लाने की तैयारी

ऐसे समय में जब दुनिया कोरोना वायरस के प्रसार से जूझ रही है, तब चीन 2022 में एक डिजिटल मुद्रा (ई आर एम बी) लाने का प्रयास कर रहा है। चीन ने यह प्रोजेक्ट 2014 में शुरू किया था। वायरस के प्रसार के दौरान ही चीन के केन्द्रिय बैंक ऑफ चाइना ने चार बड़े शहरों, शेन्जेन, चेंग्दू, सूजो और जिओन आन में इस पर तेजी दिखाते हुए कार्य किया। इसके पीछे कुछ कारण बताएं जा रहे है जिनमें अमेरिका के साथ ट्रेड वार, कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों का चीन पर आरोप लगाना और फेसबुक की डिजिटल करेंसी लिब्रा के इस साल लाने की तैयारी। विशेषज्ञों द्वारा माना जा रहा है कि इससे वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव आ सकता है। ये चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना 'बेल्ट एण्ड रोड़ इनिशिएटिव' का हिस्सा है। जिसका उद्देश्य अमेरिकी प्रभाव को खत्म करना और 21 वीं सदी का एक शक्तिशाली देश बनकर उभरना है।[16]

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि वैश्विक राजनीति में चीन इसका इस्तेमाल भू–राजनीतिक फायदे के लिए अपने 'बेल्ट एण्ड रोड़ इनिशिएटिव' प्रोजेक्ट में शामिल एशिया, अफ्रिका और यूरोप के राष्ट्रों को प्रोत्साहन पैकेज देने और निवेश करने के लिए कर सकता है। कोरोना महामारी के विवाद, ट्रेडवार और अवैश्वीकरण के कारण मुद्राजगत में अमेरिका के डॉलर का प्रभूत्व खतरे में है। वहीं भारतीय डिजीटल मुद्रा 'लक्ष्मी' और अमेरिकी 'डिजिटल डॉलर' अभी वास्तविकता से बहुर दूर है। वैसे चीन 150 से अधिक देशों को लोन दे चूका है। इसमें ज्यादातर विकासशील और अफ्रिकी देश है। अमेरिका कंसलटेंसी फर्म के अनुसार 'चीन 461 अरब डॉलर दे चूका है। चीन कर्ज देने की आक्रामक रणनीति बेहद कमजोर और जोखिम वाले देशों पर आजमा रहा है।' उसी प्रकार चीन अपनी डिजीटल मुद्रा का इस्तेमाल पहले अपना प्रभाव और फिर अपनी धौंस जमाने और वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने और

भू–राजनैतिक लाभ लेने के लिए दुनिया के देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।

कोविड–19 के संकट काल में चीन के शिंजियांग सुबे के लोपनुर में परमाणु परीक्षण 'अमेरिकी रिपोर्ट'

अभी हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अप्रैल माह में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। जिसका नाम 'शस्त्र नियंत्रण, अप्रसार और निरस्त्रीकरण की संधियों और प्रतिबद्धताओं की स्वीकार्यता और अनुपालन', इसमें यह दावें किये गए है कि चीन ने अपने शिंजियांग सूबे के लोपनुर में कम क्षमता वाले परमाणु परीक्षण किए है। जिसमें लगभग 'शून्य विकिरण' उत्पन्न होती है। अमेरिका के मुताबिक चीन ने ये परमाणु परीक्षण करके 'व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि' (सीटीबीटी) पर हस्ताक्षर करने वाले देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के लिए अपनाए जाने वाले मानकों का उल्लघंन किया है। अमेरिका ने इस पर चिंता व्यक्त की है।[17] लेकिन अमेरिका इसके ठोस सबूत नहीं दे सका है। सिरे से रिपोर्ट को नकारते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों का जिम्मेदारी से पालन करता है।

'इस समय जब पुरी दुनिया का ध्यान कोविड–19 से निपटने में लगा हुआ है तो ऐसे में यदि कोई देश इसका फायदा उठाकर परमाणु परीक्षण करता है तो इसका प्रमुख कारण ये हो सकता है कि उस देश के परमाणु हथियारों की विश्वसनीयता पर प्रश्च चिन्ह लग रहे हो।' हो सकता है ऐसे में चीन अपनी अक्षमताएं और कमियां दूर करने का प्रयास कर रहा हो। चीन के मौजूदा परमाणु जखीरे की क्षमता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे परमाणु परीक्षण करे साथ ही उसे अपने जखीरे में नए परमाणु हथियार शामिल करने के लिए भी ऐसे परमाणु परीक्षणों की जरूरत है। चीन को लगता है कि रूस और अमेरिका के मुकाबले उसका परमाणु हथियारों का जखीरा बहुत कम है लेकिन, चीन के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ईंधन है। इसकी ममद से चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने की क्षमता रखता है।[18]

वहीं इस बात के पर्याप्त सबूत है कि आंतरिक और बाहरी चुनौतियों के बावजूद चीन अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। यह चिन्ताजनक है लेकिन चौकाता बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक तरफ जहां अमेरिका और रूस परमाणु हथियारों को कम करने की दिशा में बढ़ रहे है, वहीं चीन इनकी संख्या बढ़ा रहा है। द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) के अनुसार चीन के परमाणु हथियारों के बेड़े में 2019 से 290 वॉरहैड थे, जो 2020 में बढ़कर 320 हो गए है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन का रूस अमेरिका की बराबरी के लिए 1000 न्युक्लियर वॉरहैड का लक्ष्य है। यह भी महत्वपूर्ण है कि चीन वॉशिंगटन के मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के डर के चलते अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक कर रहा है। वाशिंगटन मिसाइल का मुकाबला करने के लिए चीन मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स (एमआईआरवी) के साथ अपनी मिसाइलों को मजबूत कर रहा है। वहीं भारत के पास 150 वॉरहैड है और पाकिस्तान के पास 160 वॉरहैड है।[19]

यह भारत के लिए चिंता का विषय है क्यों कि भारत के सामने टू फ्रंटवॉर का लक्ष्य दिखाई देता है। और भारत के सापेक्ष चीन की परमाणु क्षमता बीजिंग को अधिक आक्रामक स्थिति में रखते है। ये भारत के लिए तो चुनौती है ही दुनिया के कई देश इससे प्रेरित होकर अपने परमाणु हथियारों की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर सकते है। वैसे भी चीन का परमाणु कार्यक्रम और इससे संबंधित महत्वाकांक्षा और सिस्टम को लेकर गोपनीयता अपनाए रखता है। नई तकनीक और परमारणु हथियार लाने ले जाने वाले बेहतर होते सिस्टम, और चीन का अन्य देशों से टकराव नई चुनौतियों को जन्म देता है। चीन ने अभी सीटीबीटी पर अपनी संसद से मुहर नहीं लगवाई है इसलिए अभी उसके पास विकल्प है।

चीन तकनीक का सुपरपॉवर बनना चाहता है–

आने वाले समय में चीन अमेरिका को पछाड़कर तकनीक का सुपर पॉवर बनना चाहता है। वर्ष 2015 में चीन की सरकार ने 10 वर्षों का एक विजन रखा था जिसका मकसद चीन को उद्योग और तकनीक के क्षेत्र में ताकतवर बनाना है, यानी 'मेड इन चाइना 2025'। चीन तकनीक की शक्ति पाने के लिए आविष्कार को जरूरी नहीं मानता, चीन आविष्कार में बहुत पीछे है, चीन तकनीक हासिल करके उसका इस्तेमाल करने में विश्वास करता है। चीन ने केवल अपनी रणनीति के तहत विदेशी कंपनियां खरीद रहा है बल्कि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष तरीके से तकनीक ट्रांसफर करने के दबाव भी बना रहा है। चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुपर पॉवर बन सकता है। चीन अपनी सेना में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाकर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वर्ष 2007 से चीन एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करने में लगा है, जो युद्ध के मैदान में तेजगति और सटिकता के साथ फैसला लेने में सहायक साबित होगा। अभी हाल ही में भारत ने डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 59 चीनी ऐप्स को बैन किया। चीन साइबर थ्रेट के खेल में भी आगे निकल चूका है।[20]

अमेरिका ने भी कई मौको पर चीन की कंपनियों ख्वाबे और जेडटीई को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। कई बार इस बात को लेकर भी आशंका जताई गई है कि चीनी सरकार इस कंपनी के उपकरणों की मदद से दूसरे देशों की खुफिया जानकारी हासिल कर रही है। चीन की इन दो कंपनियों पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की सेना के साथ संबंध है। अमेरिकी सरकार की संचार मामलों की नियामक संस्था फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन या एफसीसी के चेयरमैन अजित पाई के अनुसार, 'भारत में दक्षिण एशिया में, पूरी दुनिया में चीन की टेक कंपनियों को लेकर, सामान बेचने वाली ऐसी कंपनियों को लेकर जिन पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का असर है, चिंता बढ रही है।'[21]

यानी चीन तकनीक की दुनिया का मुख्य खिलाड़ी बनना चाहता है। वास्तव में चीन अपनी सेना में

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग में महारथ हासिल करना चाहता है, ताकि इसके जरिए हथियारों के प्रयोग से दूर बैठे ही भविष्य में युद्ध को नियंत्रित कर सके इससे वह युद्ध की सटिकता को बनाने के साथ ही युद्ध क्षेत्र को भी सीमित रख सकेगा। चीन इसके जरिए न केवल निगरानी रख सकेगा, बल्कि ड्रोन एवं मिसाइलों को भी संचालित कर सके। यह अत्याधुनिक तकनीक भविष्य में चीन की आक्रामकता और खतरे को बढ़ा देगा। चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी ख्वाबे दुनिया की सबसे बड़े टेलिकॉम नेटवर्क उपकरण बनाने वाली कंपनी, 5 जी नेटवर्क की तकनीक दुनिया के देशों की राष्ट्रीय सुरेक्षा को खतरे में डाल सकती है। यही नहीं चीन से खतरा इंटेलीजेंस और सायबर स्पेस का भी है। अभी लगातार सायबर हमले, हेकिंग, डेटा चोरी और जासूसी के आरोप चीन पर लग रहे है। हाल ही में अमेरिका, आस्ट्रेलिया, भारत में चीन के सायबर हमले बढ़े है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया तो चीन पर बौद्धिक संपत्ति चोरी करने के आरोप भी लगा चूके है और इसकी कुछ कंपनियों पर कार्यवाई कर चूके है। यहां तक कि चीन ने अपने रणनीतिक साथी रूस को भी नहीं छोड़ा। रूस ने भी चीन पर जाजूसी के आरोप लगाएं है। चीन ने सेन्ट्रल एशिया में न केवल दखल बढ़ाया है बल्कि रूस के प्रभाव को कम करने की कोशिश भी की है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की सेना ऐसे हर मौके का फायदा उठाना चाहेगी जिससे सामरिक फायदा हो। अतः यह स्पष्ट होता है कि चीन की तकनीक दुनिया के देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही है।

पुर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर से लेकर दक्षिण एशियाई महाद्वीप में 16 हजार फीट की ऊंचाई पर विवादित पैंगोंग झील तक चीन का आक्राकम रवैया

महामारी के दौरान चीन ने मौके का फायदा उठाकर पुर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर से लेकर दक्षिण एशियाई महाद्वीप में 16 हजार फीट की ऊंचाई पर विवादित पैंगोंग झील तक आक्रामक रूख अपना रखा है। चीन ने 3488 किमी लम्बी 'लाइन ऑफ एक्चुअल कन्ट्रोल' (एलएसी) से जुड़ी पैंगोंग त्सो झील और गलवान घाटी में अपनी सेना तैनात करके न केवल तनाव बढ़ाया है, बल्कि कई देशों को भी संकट में डाल दिया है। यह सब दिखाकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद को राष्ट्रवादी नेता के तौर पर पेश करने के लिए किया है। शी ने दुनिया को अपने स्टेण्ड पर कायम रहने का संदेश देने और अपनी राष्ट्रवादी छवि गढ़ने के लिए चीनी सैना को आगे किया।[22]

निष्कर्ष

आज चीन अपने शांतिपूर्ण उदय का मुखौटा उतार कर शक्ति की राजनीति पर उतर आया है। चीन की आक्रामकता और विस्तारवादी नीति से उसके बढ़ते दबदबे ने न केवल दुनिया के लोकतंत्र को बल्कि विश्वशांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को भी खतरें में डाल दिया है। चीन की आक्रामक और विस्तारवादी नीति से दुनिया के देशों में चीन के प्रति अविश्वास बढ़ा है। कोरोना वायरस के संकट काल में चीन के गैर–जिम्मेदाराना व्यवहार और आक्रामक निती और अमेरिका के साथ टकराव ने दुनिया को नये शीत युद्ध में धकेल दिया है। ऐसे में चीन से प्रताड़ित और उसके विरोधी देश एवं एक समान सोच रखने वाले देश चीन के खिलाफ मौर्चा खोल सकते है। अतः एक समान सोच वाले देशों को एक साथ मिलकर चीन का मुकाबला करना होगा। अतः 'क्वाड' (क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डॉयलॉग) देश एक साथ एक मंच पर आ सकते है और इसे 'क्वाड+' देशों के रूप में विस्तार कर सकते है। इसमे आशियान देश भी जुड़े सकते है। ताकि पुर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर और दक्षिण एशियाई महाद्वीप तक चीन की आक्रामक और विस्तारवादी निती से मुकाबला किया जा सके।

References

1. *Jonathan Marcus, Defence and Diplomatic Affairs Correspondence, BBC, 08 May 2019 https://www.bbc.com/hindi/international-52586799*
2. *By Nikki Heley, "There are far more dangers poses than its coronavirus actions , The Washingtonpost, 29 April 2020 https://www.washingtonpost.com/opinions/nikki-haley-chinas-coronavirus-actions-are-just-one-of-many-threats-it-poses/2020/04/29/f5eab07a-8a3c-11ea-ac8a-fe9b8088e101_story.html*
3. *Ibid*
4. *By The Associated Press, "Chaina delayed releasing coronavirus info, frustrating WHO", 03 June2020 https://apnews.com/3c0619497066/042b18d5aeaaed9fae*
5. *Tamara Gil, BBC News World, 22 Aril 2020 https://www.bbc.com/hindi/international-52357068*
6. *By Juber Ahmad, BBC Correspondent, 02 July 2020 https://www.bbc.com/hindi/international-53249483*
7. *BBC Hindi, 15 April 2020 https://www.bbc.com/hindi/international-52289148*
8. *BBC Hindi, 10 April 2020 https://www.bbc.com/hindi/international-52240504*
9. *By Elijah Wolfson, "Thrumph Said He Would Terminate The U.S. Relationship With the W.H.O. Here's What That Means", TIME, US, 04 June 2020 https://time.com/5847505/trump-withdrawl-who/*
10. *Anant Singh Mann, "Chinis defence spending in the age of covid", ORF, 07 July 2020 https://www.orfonline.org/hindi/reserch/chinis-derence-spending-in-the-age-of-covid-19-69329/*
11. *http://www.bbc.com/hindi/amp/international-46974790, 24 January 2020 By PTI, DEFENCE, China hikes defence budget to USD 179 billion, nearly three times that of India, The Economic Times, 22 May 2020*
12. *https://www.google.com/amp/s/m.economictimes.com/news/defence/china-military-budget-growth-shows-to-6-6-/amp-articleshow/75882639.cms*
13. *Team BBC, Hindi, New Delhi, 25 June 2018 https://www.bbc.com/hindi/international-44592114*

14. *Team BBC, Hindi, New Delhi, US July 2020 https://ww.bbc.com/hindi/international-44725617*
15. *Navdeep Suri, 'Popular resentment confronts China in Zambia 28 May 2020 https://www.orfonline.org/hindi/research/in-zambia-there-is-increasing-anger-against-the-policy-of-chinese-occupation-69/26/*
16. *Juber Ahmad, BBC Correspondent, 24 May 2020 https://www.bbc.com/hindi/amp/india-52776817*
17. *Julian Barger, "China may have conducted low level nucler test, US claims", The Guardian, 16 April 2020 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/16/china-may-have-conducted-low-level-nuclear-test-us-report-claims*
18. *Harsh V. Pant and Kartik Bommkanti, "Dangerous Game of nuclear test in lopenoor China", 2 April 2020 https://www.orfonline.org/hindi/reserch/dengerous-game-of-neuclear-test-in-lope-noor-china-64964/*
19. *Harsh V. Pant, Dainik Bhaskar, News Paper, 25 June 2020 Pg. 04 https://epaper.bhaskar.com/indore/129/25062020/mpcg/1*
20. *Sarve Priya Sangwan, BBC Correspondent, 02 July 2020, https://www.bbc.com/hindi/internation-53247701*
21. *Vineet Khare, BBC Correspondent, 05 July 2020 https://www.bbc.com/hindi/internation-53288410*
22. *Harsh V. Pant, Dainik Bhaskar, News Paper, 28 May 2020 Pg. 04 https://epaper.bhaskar.com/indore/129/17072020mpcg/-1/*